# राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की सितम्बर 2018 तिमाही की बैठक दिनांक 03.12.2018 का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की सितम्बर 2018 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 03.12.2018 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई.ए.एस., मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन; श्री अमित मोहन प्रसाद, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (कृषि); श्री के. रविंद्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त एवं निदेशक (उद्योग), उद्योग निदेशालय, उ.प्र.; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय; श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री ए. के. सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड; श्री अरुप कुमार, महाप्रबंधक, सिडबी की उपस्थिति प्रमुख रही। विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में डॉ रामजस यादव, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

- प्रदेश सरकार ने किसानों के उन्नयन एवं उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से तीन दिवसीय कृषि कुंभ का आयोजन किया जिसमें 70,000 से भी अधिक किसानों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग किया जिससे उन्हें कृषि क्षेत्र में विकसित हो रही नवीन तकनीकों के विषय में जानकारियां हासिल हुई। इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विश्व खाद्य दिवस (16 अक्टूबर) को पूरे भारतवर्ष में दिनांक 01.10.2018 से 16.10.2018 तक "किसान पखवाड़े" के रूप में मनाया गया जिसमें कृषकों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े बैंक के विभिन्न उत्पादों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गयी। इस दौरान देश भर में 3000 से अधिक किसान चौपालों का सफल आयोजन किया गया।
- प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों के गत वर्षों की बकाया धनराशि के भुगतान हेतु चीनी मिल मालिकों को रू. 4000 करोड़ की राशि सॉफ्ट लोन के रूप में उपलब्ध कराने की विशेष योजना लागू की गयी है जो कि प्रदेश सरकार का एक सराहनीय प्रयास है।
- दिनांक 31.10.2018 को माननीय अधीनस्थ विधान समिति, राज्य सभा द्वारा प्रदेश का भ्रमण किया गया जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह पर विस्तृत चर्चा की गयी। समिति द्वारा इस क्षेत्र में प्रदेश के बैंको द्वारा किये जा रहे प्रयासों एवं प्रदेश सरकार की नीतियों की सराहना की गई।
- प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से बैक ऑफ बड़ौदा के समन्वय में गठित उपसमिति की छठवीं बैंठक दिनांक 17.11.2018 को श्री अमित अग्रवाल, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें -457- चयनित केन्द्रों को बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने के उद्देश्य से -32- बैंकों को आवंटित किया गया जिसकी प्रक्रिया 31.03.2019 तक पूर्ण करने पर सहमति व्यक्त की गयी। बैठक में इण्डियन पोस्टल बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि दिसम्बर 2018 तक प्रदेश में लगभग -17000- डाकघरों में पोस्टल बैंक शुरू किया जाना प्रस्तावित हैं जिससे हमारे प्रदेश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार सम्भावित है।
- इसी क्रम में 2 नवंबर, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु -100- दिवसीय "एमएसएमई सहयोग एवं सम्पर्क कार्यक्रम" के अंतर्गत psbloansin59min पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अभियान को देश के 100 जिलों में शुरू किया गया है जिसमें प्रदेश के -9- जनपद यथा आगरा, फिरोज़ाबाद, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, उन्नाव, भदोही एवं वाराणसी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश के इन चयनित जिलों में प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को कैंप आयोजित किए जा रहे हैं जिसकी नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है। श्री राजीव कुमार, आई.ए.एस, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.11.2018 को सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक में इस अभियान की प्रगति समीक्षा की गयी।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में उपस्थित केन्द्र व राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं विभिन्न बैंको के वरिष्ठ कार्यपालक गणों का अभिवादन करते हुए श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में वैश्विक, राष्ट्रीय एवं प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों तथा प्रदेश में सम्पन्न विभिन्न कार्यक्रमों व उपलब्धियों से समिति को निम्नवत अवगत कराया :

- विश्व स्तर पर मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के साथ इस वर्ष यूरोजोन और जापान में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप 2019 में कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि पूर्वी यूरोप और एशिया में आर्थिक विकास में गिरावट की सम्भावना है।



बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० अंचल कार्यालय ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO. (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ

- लैटिन अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना में आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी तथा मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र अधिक आर्थिक लाभ महसूस करेंगे।
- 01.01.2019 से प्रभावी 200 बिलियन अमेरिकन डॉलर के चीनी आयात पर 25% अमेरिकी टैरिफ के लागू होने से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं शेष दुनिया मुख्य रूप से चीन के मध्य बढ़ते व्यापारिक तनाव के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट महसूस की जा रही है इसका प्रभाव मूल्य वृद्धि दर पर पड़ता है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है।
- Focus Economics Consensus Forecast के सदस्यों के अनुमान के मुताबिक गत वर्ष वैश्विक विकास दर 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो पिछले 7 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है तथा अगले वर्ष वैश्विक विकास 3.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति की दर सितम्बर 2018 में 3% से बढ़कर अक्टूबर 2018 में 3.1% हुई है जिसके कारण अमेरिका तथा यूरोजोन में मुद्रा के मूल्य में दबाव महसूस किया गया है। 2019 में वैश्विक मुद्रास्फीति 2.9% तक पहुँचने का अनुमान है।
- भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है तथा अगले 10-15 वर्षों में अपने मजबूत लोकतंत्र और साझेदारी के कारण विश्व की -3- प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाने की प्रबल सम्भावना है।
- भारत ने -4750- से अधिक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के साथ विश्व में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए अन्य महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख निम्नवत है:-

  - अप्रैल से अगस्त 2018 तक 221.83 अरब डॉलर का निर्यात दर्ज किया गया जो गत वर्ष के मुकाबले 20.7% अधिक है।
  - अगस्त 2018 तक विलय एवं अधिग्रहण (Merger & Acquisition) गतिविधियाँ 74.8 अरब डॉलर तक हो गई हैं।
  - भारतीय कंपनियों ने अगस्त 2018 तक आईपीओ के माध्यम से 21000 करोड़ रुपए (US$ 2.88 billion) का पूंजी आधार बनाया।
  - अगस्त 2018 तक खुदरा स्फीति गत 10 महीनों में सबसे कम 3.69% रही है।
  - वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में Ease of doing Business में भारत ने 30 स्थान की छलांग लगाकर खुद को 100 वें स्थान पर स्थापित किया है।
  - 2019 में विश्व बैंक के अनुसार निजी निवेश से 1.4 प्रतिशत की निजी उपभोग वृद्धि के साथ 8.1 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है जिससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायता मिलेगी।
  - भारत की राजस्व जमा 2019 तक रू 28 से 30 ट्रिलियन (US$ 385-412 बिलियन) तक पहुंचने का अनुमान है।

- उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2017 के बजट के अनुसार प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद रू 16.89 लाख करोड़ रहा।
- प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। 2011 की जनसंख्या सर्वे के अनुसार 22.30 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय इलाकों में रहती है।
- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, व्यापारियों/उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नीतियों यथा कृषि नीति, 2013; एमएसएमई नीति, 2017 तथा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक नीति, 2017 आदि का सृजन किया है व संचालित की जा रही है।
- राज्य सरकार प्रदेश में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे यथा कुशीनगर और वाराणसी बनाने के लिए कृत संकल्प है।
- राज्य सरकार ने मेरठ एवं दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण रू. 500 करोड़ की लागत से किया है।
- पूर्वी क्षेत्र के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है जिसकी अनुमानित लागत रू. 11,200 करोड़ है।
- प्रदेश सरकार की अलीगढ़ से बुंदेलखंड की परियोजना डिफेंस कॉरिडोर के नाम से प्रस्तावित है जिसका उद्देश्य प्रदेश में रक्षा सामग्री का उत्पादन करना है।
- राज्य सरकार द्वारा पांच मेट्रो रेल परियोजनाओं की स्थापना प्रस्तावित है जिसमें मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी एवं लखनऊ केन्द्र शामिल है तथा लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना प्रारंभ भी हो चुकी है।
- इन्वेस्टर्स समिट, 2018 की अनुवर्ती कार्यवाही स्वरूप पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में आयोजित की गई जिसमें लगभग रू. 61,000 करोड़ की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश में बैंकों को ऋण जमानुपात बढाने का अवसर प्राप्त होगा।
- गत 10.08.2018 को "एक जनपद एक उत्पाद" समिट का आयोजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम के क्रियांवयन से प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग -5- लाख रोज़गार का सृजन होने का अनुमान है। इन दोनो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगामी वर्षों में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर पहुँचने की भी सम्भावना है।



बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0 अंचल कार्यालय (पू0उ0प्र0 अंचल), लखनऊ ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE), LKO.

तत्पश्चात कार्यकारी निदेशक महोदय द्वारा निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर राज्य की उपलब्धियों से अवगत कराया :

- सितम्बर 2018 तिमाही तक प्रदेश का कुल जमा एवं अग्रिम क्रमशः रू.956118.25 करोड़ तथा रु. 488887.81 करोड़ है जो जून 2018 त्रैमास की अपेक्षा रू. 24745.80 करोड़ एवं रु. 17349.61 करोड़ क्रमशः की वृद्धि को दर्शाता है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि एवं कमजोर वर्ग के अंतर्गत क्रमशः 59.37%, 27.7% तथा 18.64% ऋण प्रदान किया गया है जो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानको 40%, 18% तथा 10 % से अधिक है।
- वार्षिक ऋण योजना 2018-19 हेतु वार्षिक लक्ष्यों रु. 229656.41 करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा समीक्षा अवधि तक रु. 90686.49 करोड़ (39.49%) की राशि वितरित की गयी है जो गत वर्ष की समान अवधि की उपलब्धि रू 77808.63 करोड़ (38.72%) के सापेक्ष रू 12877.86 करोड़ ( 16.55%) अधिक रही है।
- भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रति -10- शाखाओं पर कम से कम एक बैंक शाखा को आधार नामांकन केन्द्र के रूप में अधिकृत किया जाना है। इस क्रम में प्रदेश में कुल -1805- बैंक शाखाओं का चयन किया गया है जिसमें से -1702- शाखाएँ वांछित सेवाएँ प्रदान कर रही है।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्य -39- लाख के सापेक्ष द्वितीय तिमाही तक कुल 31.58 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके है।
- प्रदेश का ऋण जमा अनुपात सितंबर 2018 में 51.13% रहा है जबकि जून 2018 तिमाही में यह 50.63% था। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं और नवोन्मेषी कार्यक्रमों के लागू होने से इसमें निश्चय ही वृद्धि होगी।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत प्रदेश में वार्षिक लक्ष्य रू.14698.45 करोड़ के सापेक्ष 30.11.2018 तक रू. 7921.40 करोड़ (53.89%) का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। स्टैंड अप इंडिया योजनांतर्गत प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष आशानुरूप नहीं रही है।
- कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंक बकाया राशि की स्थिति क्रमशः 66.06% एवं 65.45% है जो गत वर्ष की समान अवधि (क्रमशः 64.95% एवं 64.69%) की तुलना में बेहतर हुई है। प्रदेश में ऋण वसूली हेतु -884761- वसूली प्रमाण पत्र रू. 6163.54 करोड़ के लम्बित हैं। चालू वर्ष के दौरान वसूली प्रमाण पत्रों में कुल बकाया के सापेक्ष रू. 158.65 करोड़ की धनराशि की वसूली हुई है जो अपेक्षाकृत कम है। प्रदेश सरकार के सहयोग से सरफेसी एक्ट , 2002 के अंतर्गत दर्ज व जिलाधिकारी की अनुमति हेतु मार्च 2018 तक लम्बित -2064- मामलो की संख्या में कमी आई है जो अक्टूबर 2018 तक -1791- रह गयी है। परंतु अभी भी लगभग -1200- प्रकरण ऐसे हैं जो वैधानिक समय सीमा से अधिक अवधि से लंबित है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

अंत में उन्होंने प्रदेश सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंको तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किये जा रहे समंवित सहयोग हेतु सभी का धन्यवाद दिया व अनुरोध किया कि विभिन्न एजेंसीज से समय समय पर जारी सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने समस्त विभागों के मध्य सूचनाओं के पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से आदान प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ अनूप चंद्र पाण्डेय, आई.ए.एस., माननीय मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य अतिथियों को संबोधित करते हुए निम्नानुसार अपने विचार रखे :

- एसएलबीसी की कार्यप्रणाली तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों में बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग की प्रशंसा की। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाई जाने वाली नई योजनाओं में बैंकों द्वारा प्रदान किये जा रहे निरंतर सहयोग की सराहना करते हुए उन्होने कहा कि हमारे प्रदेश की एसएलबीसी द्वारा किए गए कार्यों की अन्य प्रदेशों में भी प्रशंसा होती है।
- प्रदेश में निवेश की अपार सम्भावनाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश सरकर द्वारा फरवरी 2018 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में रू.4,28,000 करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान लगभग रू. 62,000 करोड़ धनराशि के एमओयू में से अधिकांश मामलो मे कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इससे उत्साहित होकर प्रदेश सरकार नें अगले 2 माह के दौरान लगभग रू 1.00 लाख करोड़ के और एम.ओ.यू की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने की योजना बनाई है।
- अनेक महत्वपूर्ण व्यवसायिक घराने व ग्रुप्स प्रदेश में अपनी इकाईयाँ स्थापित करने के इच्छुक है जो निश्चय ही बैंकर्स के लिए निवेश बढाने के लिए अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु परियोजना लागत लगभग रु 15 हजार करोड़ में प्रदेश के कार्यरत बैंकों द्वारा ही निवेश किया जा रहा है।



बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO. अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ

- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट का विस्तार, मेगा लॉजिस्टिक पार्क, पॉवर सेक्टर की योजनाओं व आयुष्मान भारत इत्यादि अनेक परियोजनाओं पर कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है जिसमें बैंकर्स द्वारा निवेश की अपार सम्भावनाएं विद्यमान है जो अंततः प्रदेश के ऋण जमानुपात को बढाने में सहायक सिद्ध होगा।
- अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने अवगत कराया कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर स्थापित कर समस्त ग्राम पंचायतों को प्रदेश मुख्यालय से जोड़ने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।
- बेहतर मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कम्पनियों यथा आइकिया व अमेजॉन के साथ एम.ओ.यू. किये है ताकि प्रदेश में निर्मित माल को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय मार्केट में स्थान प्राप्त हो सके।
- प्रदेश के विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लगभग 21 नीतियाँ बनाई गयी है।
- गत 40 वर्षों से लम्बी सरयू परियोजना पर इस वर्ष कार्य पूर्ण होने की पूर्ण सम्भावना है जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं रहेगी।
- आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांवों में 1,90,000 आवास निर्मित कराये गये हैं साथ ही शहरी क्षेत्रों हेतु भी इस योजना पर कार्य किया जा रहा है।
- एमएसएमई योजना प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। इसके विस्तार की अपार सम्भावनाएँ है अत: इस कार्य हेतु संचालित की जा रही नवीन योजना व psb59minute पोर्टल का उपयोग करें।
- उन्होंने सुझाव दिया कि मुद्रा योजना को ओ.डी.पी. योजना से जोड़ दिया जाए तो मुद्रा योजना की प्रगति 100 से अधिक परिलक्षित होगी।

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होंने सभा में उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए सार्थक चर्चा हेतु अपनी शुभकामनाएँ दी।

श्री अमित मोहन प्रसाद, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (कृषि), उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन के दौरान प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था व किसानों की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए उनके उत्थान हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहयोग प्रदान करने का आह्वाहन किया।

दिनांक 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2018 तक लखनऊ में आयोजित कृषि कुंभ का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के सक्रिय सहयोग व समंवय के कारण ही सम्भव हो सका जिसमें पूरे देश से लगभग 1 लाख किसानों व अन्य व्यक्तियों की सक्रिय सहभागिता हुई। इस समागम का लाभ विभिन्न वर्गो द्वारा महसूस किया गया है और एक अच्छा फ़ीडबैक प्राप्त हो रहा है जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है।

इसी क्रम में उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मिलियन फार्मर स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से प्रदेश सरकार 10 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का तीसरा सत्र प्रारंभ होने वाला है।

प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एग्री जंक्शन योजनांतर्गत उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना करी।

श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

- कुछ जनपदों यथा बहराइच, हमीरपुर, सोनभद्र, मुरादाबाद तथा सम्भल इत्यादि में सितम्बर 2018 की त्रैमासिक डी.सी.सी./ डी.एल.आर.सी. बैठको का आयोजन न हो सकने की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि यदि जनपद स्तर पर इन बैठको के आयोजन में कोई समस्या आ रही है तो अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा इसकी सूचना से भारतीय रिजर्व बैंक को अवगत किया जाये ताकि इसका समाधान किया जा सके। उन्होंने इन महत्वपूर्ण बैठको के नियमित आयोजन व इनमें सार्थक चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि सभी जनपदों वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर उसके अनुसार बैठको का आयोजन किया जाये।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में विभिन्न सम्भावनाशील जनपदों में कम ऋण जमा अनुपात के कारणों पर एक सर्वे कराया गया। इस सर्वे की महत्वपूर्ण परिणामों के अनुरूप बैंको द्वारा small loan finance को बढ़ाया जाना चाहिए तथा इसके अनुरूप सभी शाखाओं को जागरूक किया जाये। सर्वे के दौरान यह बात भी प्रकाश में आयी है कि इन जनपदों में ऋण प्रदान करने के प्रचुर अवसर मौजूद है तथा NBFCs/ MFIs द्वारा अनौपचारिक रूप से ऋण वितरण किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में वित्तीय साक्षरता का अत्याधिक महत्व है।



बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.U.P. ZONE) LKO. अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ

श्री ए. के. सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अपने सम्बोधन में कहा कि एग्री मार्केटिंग स्कीम जो गत तीन वर्षो से बन्द थी उसे भारत सरकार द्वारा पुन: प्रारम्भ कर दिया गया है तथा सब्सिडी भी जारी कर दी गयी है। नाबार्ड द्वारा इस सन्दर्भ में सभी बैंको को यथानुसार सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है जो जल्द ही एक्टिव हो जायेगा। वर्तमान में सभी सम्बन्धित को सब्सिडी क्लेम करने के लिए physical form मे ही आवेदन करना होगा। उल्लेखनीय है कि इस स्कीम के अंतर्गत एग्री मार्केटिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियाँ कवरड है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने के अभियान हेतु यह भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है अत: इस योजनांतर्गत सभी सम्बन्धित का सक्रिय योगदान महत्वपूर्ण है।

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 24.08.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

गत बैठक दिनांक 24.08.2018 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी। उक्त कार्यवृत्त में कोई संसोधन या सुझाव प्राप्त नहीं हुए |

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 24.08.2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट**

1. **वसूली प्रमाण पत्रों तथा सरफेसी अधिनियम , 2002 के अंतर्गत जारी नोटिसों के सापेक्ष जिलाधिकारियों को प्रेषित आवेदन पत्रों के समयानुसार निस्तारण से सम्बन्धित :**

सदन को अवगत कराया गया कि इन दोनों मामलो से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है जिसके क्रम में संस्थागत वित्त निदेशालय द्वारा प्रभावी निर्देश भी जारी किये गये है। यद्यपि इन निर्देशों के अनुपालन से अच्छे परिणाम परिलक्षित हुए है तथापि पुन: यथानुसार निर्देशों की पुन: आवश्यकता है। दिनांक 27.09.2018 को सम्बन्धित विषयक एस.एल.बी.सी. की उपसमिति की बैठक इलाहाबाद बैंक के संयोजन में आयोजित की गयी। सभी बैंकर्स से अनुरोध दोहराया गया कि राजस्व परिषद से सम्बन्धित प्रकरणों हेतु वे सतत सम्पर्क बनाये रखे।

2. **बैंको में व्यवसाय प्रतिनिधियों (Business Correspondents) की कार्यशैली एवं उनके विवरण को शाखाओं में यथास्थान प्रदर्शित किया जाना :**

अवगत कराया गया कि एस.एल.बी.सी. द्वारा इस दिशा में सभी सम्बन्धित से पत्राचार व अनुश्रवण किया गया है तथा -5- बैंको द्वारा तदनुसार कार्यवाही की जा चुकी है। अन्य बैंको द्वारा भी इस कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु अनुरोध दोहराया गया।

3. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रभावी रूप से क्रियांवयन एवं स्टैण्ड अप इण्डिया योजना की प्रगति तथा निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु प्रभावी कदम उठाना :**

इन योजनाओं से सम्बन्धित अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

4. **प्रधानमंत्री आवास योजना:**

योजनांतर्गत सितम्बर 2018 को समाप्त अवधि तक -19068- मामलों में ऋण वितरण की जानकारी से सदन को अवगत कराया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इस योजना के कार्यांवयन की नियमित समीक्षा कर रही है। यह भी अवगत कराया गया कि नोडल एजेंसी हुडको द्वारा बैंको को -480- नगर निकाय/ टाउन एरिया के व्यक्तिगत लाभार्थियों की सूचना प्रेषित की गयी है। यह सूची एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी बैंको को प्रेषित की जा चुकी है। बैंको द्वारा इन प्रकरणों पर पात्रता अनुसार ऋण स्वीकृति व वितरण की आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध दोहराया गया।

5. **पीएमजेडीवाई खातो में रुपे कार्ड का वितरण व सक्रियण :**

प्रधानमंत्री जन धन खातो में रूपे कार्ड के वितरण व सक्रियकरण में गैप के मामलो को एस.एल.बी.सी. के पत्रांक LZ/44/SLBC/FI/286 दिनांक 13.09.2018 के माध्यम से सभी बैंको को अवगत कराया गया है। ईमेल और टेलिफोनिक रिमाइंडर के द्वारा इस गैप को कम किया गया है तथा विभिन्न बैंक इस मुद्दे को हल करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।



बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO. अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ

## कार्यसूची संख्या – 1
## वित्तीय समावेशन पहल की समीक्षा, बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार और वित्तीय साक्षरता

### (क) बैंक रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट एवं बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में सीबीएस, इनेबल्ड बैंकिंग आउटलेट खोलने की स्थिति

समिति को अवगत कराया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के समन्वय में एक उपसमिति बनी है। इसकी अंतिम बैठक 17 नवम्बर 2018 श्री अमित अग्रवाल, आई. ए. एस. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार प्रथम चरण में हमारे प्रदेश के -5000- से अधिक आबादी वाले -571- केन्द्रों को चिन्हित किया गया था जिसमे शत प्रतिशत बैंकिंग सुविधाओ को पहुँचा दिया गया है। द्वितीय चरण में चयनित -1643- केन्द्रों को चिन्हित किया गया था। इन सभी केन्द्रों पर अग्रणी जिला प्रबन्धकों/ बैंको द्वारा सर्वे करने के उपरांत -457- केन्द्रों पर बैंकिंग आउटलेट्स स्थापित करने का रोडमैप तैयार किया गया है जिसका बैंकवार आवंटन कर दिया गया है। इन चिन्हित केन्द्रों पर सम्बंधित बैंक द्वारा 31.03.2019 तक बैंकिंग आउटलेट्स खोलने की समय सीमा तय की है। चर्चा के दौरान Indian Postal Bank के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि दिसम्बर 2018 तक पोस्टल बैंक की लगभग -17,000- बैंक शाखाएँ पूरे प्रदेश में कंवर्ट किया जाना प्रस्तावित है जो इस कार्य को गति प्रदान करेंगा।

### वित्तीय समावेशन
### 1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी. एम. जे. डी. वाई.)

दिनांक 15.08.2014 को प्रारम्भ की गई योजना में अब तक 5.16 करोड़ खाते खोले जा चुके है। इनमें से 4.64 करोड़ सक्रिय खातों में राशि जमा हुई तथा 4.04 करोड़ रूपे कार्ड जारी किये जा चुके है। 83.95% खातों में आधार सीडिंग की जा चुकी है। व्यवसाय प्रतिनिधियों को Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) से सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध कराये गये है। शेष 1.12 करोड़ खातो में भी रूपे कार्ड जारी करने हेतु समस्त बैंको से अनुरोध किया गया।

### 2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) एवं अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएँ यथा “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना” व “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना” के अंतर्गत प्रदेश में बैंको द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों के निस्तारण पर बैंको, बीमा कम्पनियों मे त्वरित गति से कार्य करने का निर्णय लिया गया। सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हमारा प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में हमारा द्वितीय स्थान पर है।

### 3. अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर एवं स्वरोजगारी व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु उपरांत उन्हें पेंशन उपलब्ध कराना है। अवगत कराया गया कि PFRDA द्वारा समय समय पर इस योजना के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न अभियान चलाये गये जिसमें सभी सदस्य बैंको ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। हमारे प्रदेश ने पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

### 4. सम्भावनाशील जनपद (Aspirational Districts)

भारत सरकार द्वारा देश में -115- पिछड़े जनपदों को Aspirational Districts परिभाषित किया गया है तथा चयनित विकास आवश्यकताओं को पूरा कर उनके सर्वांगीण विकास हेतु चिन्हित किया गया है। इन -115- जनपदों में से -8- जनपद यथा चित्रकूट, सोनभद्र, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती (इलाहाबाद बैंक), फतेहपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा), सिद्धार्थनगर (भारतीय स्टेट बैंक) व चन्दौली (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया) हमारे प्रदेश से सम्बन्धित हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन चिन्हित जनपदों में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रगति की निगरानी हेतु निर्धारित -5- मानकों व प्रत्येक मानक हेतु केपीआई (Key Performance Indicator) से अवगत कराया गया था। सभा को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत प्रगति लक्ष्य से अधिक दर्ज हुई है।

### (ख) बैंक मित्रों के संचालन की समीक्षा - बाधाएँ एवं मुद्दे

सदन को अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया।



बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.U.P. ZONE) LKO. अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल)

### (ग) डिजिटल बैंकिंग – प्रदेश में डिजिटल मोड से भुगतान में वृद्धि, कनेक्टिविटी समस्याएँ आदि

विमुद्रीकरण के पश्चात कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने हेतु बैंको ने आधार युक्त जमा भुगतान एवं रूपे कार्ड आधारित जमा भुगतान शुरू किया है। साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंको द्वारा मोबाइल बैंकिंग, यू.पी.आई. (Unified Payment Gateway); भीम (Bhim) इत्यादि सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जा रही है।

बैंको को अपने स्तर पर इलेक्ट्रानिकली ट्रांजेक्शन यथा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./आई.एम.पी.एस. क्रेडिट व डेबिट कार्ड, पांइट ऑफ सेल, आधार आदि से पूर्ण करना है। वर्ष 2018-19 हेतु प्रदेश के कुल वार्षिक लक्ष्यों का एजेंसीवार विभाजन लम्बित है। प्रसंगवश, समीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न बैंको द्वारा लगभग 66.33 करोड़ ट्रांजेक्शन्स किये जा चुके हैं।

### (घ) प्रत्यक्ष बेनिफिट स्थानांतरण के रोलआउट, आधार सीडिंग एवं अधिप्रमाणन की स्थिति

प्रदेश में -1805- बैंक शाखाएँ चिन्हित की गई जिसमें -1702- केन्द्रो पर आधार पंजीकरण का कार्य चल रहा है। आधार कार्यालय से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। समिति में उपस्थित सभी सम्बन्धित को केन्द्र सरकार की अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु खाते में आधार प्रवष्टि तथा अधिप्रमाणन की आवश्यकता के बारे में अवगत कराते हुए इसका अनुपालन करने हेतु अनुरोध दोहराया गया।

### (ड) वित्तीय साक्षरता - स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करने की समीक्षा, बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता पहल (विशेष रूप से डिजिटल वित्तीय साक्षरता)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में अंगीकृत -9,649- स्कूलो में -10,592- प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर अब तक -5,09,089- विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की जा चुकी है।

### (च) विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी, सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना फसल बीमा, नवीकरणीय ऊर्जा

बैंको द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी से अवगत कराया गया कि विभिन्न माध्यमों, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

### (छ) आपूर्ति श्रृंखला में सभी हितधारकों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के अंत तक प्रयासों की समीक्षा

यह एक नई संकल्पना उभरकर आई है अत: इसमें सभी सम्बन्धित सहभागियों के सहयोग का अनुरोध किया गया।

## कार्यसूची संख्या 2
## बैंकों द्वारा ऋण वितरण की समीक्षा

### (क) प्रदेश की वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्धि

समिति के समक्ष अद्यतन प्रगति प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार आवंटित कुल वार्षिक लक्ष्यों रू 229656.41 करोड़ के सापेक्ष रू. 90686.49 करोड़ की उपलब्धि (39.49%) से अवगत कराया गया।

### अन्य कृषि व्यवसाय सम्बन्धित योजनाएँ

### 1. भारत के पूर्वी प्रदेशों में भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हरित क्रांति योजना के अंतर्गत कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों में इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है। Revamped Lead Bank Scheme के अंतर्गत अब यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के स्थान पर इस उपसमिति का संयोजन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा किया जा रहा है। इस उपसमिति की बैठक दिनांक 20.11.2018 को आयोजित की गयी थी।

### 2. एग्रीक्लीनिक/ एग्रीबिज़नेस केन्द्र

अवगत कराया गया कि बैंकों योजनांतर्गत 195 मामलों में ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

### 3. ग्रामीण भंडारण हेतु कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह योजना लागू की गयी है। योजनांतर्गत कार्यवाही हेतु बैंकर्स से अनुरोध किया गया।

3. प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों के बकाया धनराशि के भुगतान हेतु तैयार " सॉफ्ट लोन स्कीम " :

प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों की बकाया धनराशि के भुगतान करने के उद्देश्य से एक विशेष योजना - सॉफ्ट लोन स्कीम तैयार कर उसका क्रियांवयन किया जा रहा है। योजना के प्रावधानों के अंतर्गत रू 4000 करोड़ की धनराशि गन्ना मिल मालिकों को उनके किसानों के बकाया देय के भुगतान के उद्देश्य से दिया जाना प्रस्तावित है। यह धनराशि विभिन्न बैंको के माध्यम से दी जानी है तथा इसमें बैंको की भूमिका फण्ड मैनेजर की रहेगी। इस योजना के सफल क्रियांवयन से सम्बन्धित विभिन्न बैठके प्रदेश सरकार एवं बैंको के बीच की जा चुकी है।

(ख) सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रवाह एवं इन योजनाओं का प्रभाव

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM)

योजना 39 जनपदों में 250 विकासखंडों में सघन रूप से चल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने State NRLM के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है तथा अन्य बैंक एवं ग्रामीण बैंक भी इस ओर अग्रसर है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य -37537- के सापेक्ष -11795- स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषित किया गया।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihood Mission- NULM)

योजनांतर्गत दर्ज अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

इस रोजगार परक योजना का संचालन के.वी.आई.सी. नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु बैंको से अनुरोध किया गया। अपने सम्बोधन में श्री के रवीन्द्र नाइक, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उ.प्र., कानपुर द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया :

- गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्वीकृत सभी मामलों में ऋण वितरण की कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण किया जाना,
- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु शाखाओं को प्रेषित सभी ऋण मामलों में निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना,
- सभी लम्बित प्रकरणों में मार्जिन मनी दावो का नोडल शाखा – कारपोरेशन बैंक, मुम्बई को प्रेषण किया जाना तथा सम्बन्धित खातों में फ़ीड करना,
- सभी स्वीकृत प्रकरणों में सम्बन्धित ट्रेनिंग की कार्यवाही को पूर्ण करते हुए ऋण वितरण में तेजी लाया जाना,

श्री नाइक ने एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत ऋण प्रवाह में तेजी के उद्देश्य से वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के अंतर्गत इस सेक्टर के आवंटित लक्ष्यों को बढ़ाकर रू 75,000/- करोड़ किये जाने तथा इसकी उपलब्धि हेतु सभी सम्बन्धित से अनुरोध दोहराया। उन्होंने एम.एस.एम.ई. सेक्टर की अन्य योजनाओं के क्रियांवयन के सम्बन्ध में भी चर्चा की।

चर्चा के दौरान इस योजनांतर्गत ऋण वसूली की कार्यवाही में नोडल एजेंसी के सहयोग का अनुरोध दोहराया गया क्योंकि अभी तक योजनांतर्गत ऋण वसूली की स्थिति असंतोषजनक है।

विशेष समन्वित योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

इन योजनाओं की प्रगति समिति के समक्ष रखी गई।

अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता

सन्दर्भित योजनांतर्गत अद्यतन प्रगति से समिति को अवगत कराया गया।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

समिति को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत प्रदेश में वार्षिक लक्ष्य रू.14698.45 करोड़ के सापेक्ष 30.11.2018 तक रू. 7921.40 करोड़ (53.89%) का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर समुदाय हेतु Revival, Reform & Restructuring Package का क्रियांवयन – प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना

इस कार्यक्रम के क्रियांवयन एवं मूल्यांकन हेतु एस.एल.बी.सी. की एक सब कमेटी सिंडीकेट बैंक के समन्वय में गठित है, जिसकी नियमित बैंठक आयोजित कर प्रगति समीक्षा की जाती है। सम्बन्धित बैंको से अनुरोध किया गया कि लम्बित आवेदन पत्रों का



बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO. अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ

निस्तारण अविलम्ब कराये ताकि बुनकरों को ससमय आर्थिक लाभ प्राप्त हो एवं वे अपना कारोबार कर सके।

स्टैंण्ड अप इण्डिया योजना

स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत प्रगति संतोषजनक नही है। सभी सम्बन्धित से अनुरोध किया गया कि इस योजनांतर्गत आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सघन प्रयास किये जाये।

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम

इस कार्यक्रम की शुरुआत 25.01.2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। दिनांक 10.08.2018 एवं 28.10.2018 को दो वृहद कार्यक्रमों का आयोजन माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हो चुका है जिनमें रू 1000 करोड़ से अधिक की ऋण राशि का वितरण किया गया। इसी प्रकार के अन्य कैम्प्स विभिन्न जनपदों में आयोजित करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें बैंको व सम्बन्धित जनपदों के अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता व सहयोग आवश्यक है।

(ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह

उक्त योजना भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा लागू की गई तथा 2 अक्टूबर 2006 से प्रारम्भ की गई । विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत उद्यमों के विकास की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा Empowered Committee के माध्यम से की जा रही है। योजनांतर्गत बैंको द्वारा किये जा रहे ऋणों की स्थिति पर सदन में विस्तृत चर्चा की गयी।

उद्योग निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदवार पोटेंशियल का आंकलन करते हुए एम.एस.एम.ई. सेक्टर हेतु आवंटित कुल वार्षिक लक्ष्य रू 41401.85 करोड़ को बढ़ाकर रू 75000 करोड़ करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

100 Days MSME Support & Outreach Programme

एम.एस.एम.ई. सेक्टर में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किये गये 100 दिवसीय एम.एस.एम.ई. सहयोग एवं सम्पर्क कार्यक्रम में समस्त सम्बन्धित से आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना:

योजनांतर्गत अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

(घ) किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा

सदन को योजनांतर्गत प्रगति से अवगत कराया गया। प्रगति के अनुसार 12 लाख केसीसी जारी किए जा चुके हैं। दुर्घटना बीमा योजना व्यक्तिगत रूप से किसानों पर लागू होती है तथा फसल बीमा फसलों के लिए तैयार की गई है। हर सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फसल बीमा से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय एवं सभी बैंकों तथा बीमा कंपनियों के साथ होती है तथा कमियों का समाधान भी होता है।

(ड) शिक्षा ऋण

योजनांतर्गत प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में सितम्बर 2018 तक कुल -14528- विद्यार्थियों को रू 457.49 को धनराशि वितरित की गयी।

(च) स्वयं सहायता समूह

सदन को योजनांतर्गत प्रगति से अवगत कराया गया।

साहूकारी ऋण मुक्ति योजना

सदन को योजनांतर्गत प्रगति से अवगत कराया गया।



बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0 ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO. अंचल कार्यालय (पू0उ0प्र0 अंचल), लखनऊ

## कार्यसूची संख्या 3

## 2022 तक किसानों की आय का दोगुना

Revamped Lead Bank Scheme का यह एक प्रमुख एजेण्डा बिन्दु है। नाबार्ड द्वारा इस विषय पर अनेक प्रयास किये जा रहे है यथा उत्पादकता, जलसंचय एवं कृषि नीतियों में सुधार, एकीकृत कृषि प्रणाली, बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करना एवं विशेष नीतिगत उपाय/ नीतियाँ इत्यादि जिनकों अपनाकर किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। इन बिन्दुओं पर सदन द्वारा चर्चा की गयी।

## कार्यसूची संख्या 4

## ऋण जमा अनुपात, 40% से कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों की समीक्षा और डीसीसी (एससीसी) की विशेष उप-समितियों के कामकाज

प्रदेश में 23 जनपद ऐसे है जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है। इस विषय पर सदन में व्यापक चर्चा हुई तथा इसमें सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए समस्त से अनुरोध किया गया। इन जनपदों की समीक्षा बैठक यूनियन बैंक के समन्वयन गठित उपसमिति में अभी तक होती रही है। आशा व्यक्त की गई कि एक जनपद एक उत्पाद, मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना एवं प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही विभिन्न परियोजनाओं में निवेश से ऋण जमानुपात की स्थिति बेहतर होगी। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानकों के सापेक्ष प्रदेश का निवेश अच्छा है। सितम्बर 2018 में ऋण जमा अनुपात 51.13% दर्ज हुआ जो मार्च 2018 के सापेक्ष 2.10% कम है।

## कार्यसूची संख्या 5

## विभिन्न योजनाओं में गैर निष्पादक आस्तियों, प्रमाणपत्र मामले और गैर निष्पादक आस्तियों की वसूली की स्थिति

एन.पी.ए. की वर्तमान स्थिति तथा वसूली से संबंधित आंकड़ों से समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया। समिति को अवगत कराया गया कि वसूली आदि पर पूर्व में चर्चा हुई तथा Action Taken Report के माध्यम से लंबित वसूली प्रमाण पत्र तथा सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत जिला अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर चर्चा हुई तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के साथ साथ और सहयोग का अनुरोध किया गया।

## कार्यसूची संख्या 6

## राज्य में प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिलों में ऋण के पुनर्गठन की समीक्षा, यदि कोई हो

समीक्षा अवधि में यह सूचना शून्य रही है।

## कार्यसूची संख्या 7

## केन्द्र/ राज्य सरकार /भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत पहलों पर चर्चा (औद्योगिक नीति, एमएसएमई नीति, कृषि नीति, स्टार्ट-अप पॉलिसी, आदि) और बैंकों के उम्मीद की भागीदारी

जैसा कि एजेण्डा की विषय वस्तु से ही स्पष्ट है कि इस कार्य बिन्दु में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी विभिन्न नीतियों की प्रदेश के विकास में उपयोगिता, उनके कार्यांवयन तथा परिणामों की सामीक्षा होना प्रस्तावित है। इन नीतियों के अंतर्गत सघन प्रयास कर बहुमुखी विकास प्राप्त करना ही उद्देश्य है।

## कार्यसूची संख्या 8

## ग्रामीण बुनियादी ढांचे / क्रेडिट अवशोषण क्षमता में सुधार पर चर्चा

विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही सम्बन्धित एजेंसीज से अनुरोध भी किया गया कि निम्न विषयों पर उपलब्ध जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :

(क) सी-डी में सुधार करने में मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा कल्पना की गई कोई भी बड़ी परियोजना अनुपात
(ख) राज्य-विशिष्ट संभावित विकास क्षेत्रों और आगे के रास्ते के दायरे का अन्वेषण करें - पार्टनर बैंकों का चयन करना
(ग) क्षेत्र केंद्रित केंद्रित अध्ययनों, यदि कोई हो, और सुझाए गए समाधानों को लागू करने पर निष्कर्षों पर चर्चा



बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल) लखनऊ ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO.

(घ) ग्रामीण और कृषि के बुनियादी ढांचे में अंतराल जो वित्तपोषण की जरूरत है (ग्रामीण गोदाम, सौर ऊर्जा, कृषि प्रसंस्करण, बागवानी, संबद्ध गतिविधियों, कृषि विपणन आदि) की पहचान

(ड़) मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 का कार्यान्वयन (संभावना की खोज)

## कार्यसूची संख्या 9

## कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) आदि के साथ भागीदारी मिशन मिशन पर कौशल विकास की दिशा में प्रयास आरएसटीआई के कामकाज की समीक्षा सहित

विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही सम्बन्धित एजेंसी से अनुरोध भी किया गया कि इस विषय में उपलब्ध जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

### आरसेटी संस्थानों की स्थापना

प्रदेश में कुल 76 आरसेटी संस्थान कार्यरत है। आरसेटी संस्थानों के क्रियाकलापो तथा प्रगति समीक्षा हेतु पंजाब नेशनल बैंक के समंवय में एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति गठित है जिसकी नियमित बैठके की जा रही है। अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

## कार्यसूची संख्या 10

## भूमि रिकॉर्ड में सुधार के लिए कदम उठाए गए, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में प्रगति और निर्बाध ऋण वितरण

इस विषय पर राज्य सरकार के स्तर से विस्तृत स्थिति, डाटा एवं कार्यबिन्दु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही बैंको के स्तर पर ऑनलाइन सूचना प्रदान करने व भूमि के प्रभार के पंजीकरण ऑनलाइन कराने आदि हेतु सुझाव समिति के समक्ष रखा गया।

## कार्यसूची संख्या 11

## जिला स्तर पर सफलता की कहानियों और नई पहलों को साझा करना जिन्हें अन्य जिलों या राज्य में दोहराया जा सकता है

विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही समस्त बैंको से अनुरोध किया गया कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों की सफलता की कहानियाँ प्रत्येक त्रैमासांत एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करने का कष्ट करे।

## कार्यसूची संख्या 12

## बाजार खुफिया मुद्दों पर चर्चा

विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही सम्बन्धित एजेंसी से अनुरोध भी किया गया कि इस विषय में उपलब्ध जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(क) पोंजी योजनाएं/ असंगठित निकायों/ फर्मों/ कंपनियों की अवैध गतिविधियां जनता से जमा की मांग

(ख) बैंकिंग संबंधित साइबर धोखाधड़ी, फिशिंग, आदि

(ग) क्षेत्र में उधार संस्थाओं, ऋणात्मकता के मामलों के द्वारा उदार गतिविधियों के उदाहरण

(घ) उधारकर्ता समूहों, आदि द्वारा क्रेडिट से संबंधित धोखाधड़ी

### बैंकों से सम्बन्धित अपराधिक मामले :

चर्चा के दौरान बैंको से प्राप्त -6- आपराधिक मामले समिति के समक्ष रखे गये (बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक- 4; बैंक ऑफ बड़ौदा- 1 व प्रथमा बैंक- 1 ) इन आपराधिक मामलों की स्थिति से समिति को अवगत कराया गया। पुलिस विभाग से अद्यतन जानकारी का अनुरोध किया गया है।



बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO.

## कार्यसूची संख्या 13

## डीसीसी / डीएलआरसी बैठक में अनसुलझे मुद्दे शेष

विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही सम्बन्धित एजेंसी से अनुरोध भी किया गया कि इस विषय में उपलब्ध जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि द्वारा समस्त सम्बन्धित से अनुरोध किया गया कि सभी जनपदों में डी.एल.आर.सी./डी.सी.सी. बैठको का आयोजन निर्धारित समयसीमा के भीतर कराना सुनिश्चित किया जाये।

## कार्यसूची संख्या 14

## एसएलबीसी बैठक के अनुसूची का पालन करते हुए बैंक द्वारा समय पर डेटा जमा करना

विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही सम्बन्धित एजेंसी से अनुरोध भी किया गया कि इस विषय में उपलब्ध जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

## कार्यसूची संख्या 15

## अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई अन्य वस्तु

एम.एस.एम.ई. सेक्टर में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किये गये 100 दिवसीय एम.एस.एम.ई. सहयोग एवं सम्पर्क कार्यक्रम में समस्त सम्बन्धित से आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया।

बैठक के अंत में श्री संजीव गुप्ता, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी आमंत्रित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.U.P. ZONE) LKO. अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ

## राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 03.12.2018 - कार्य बिन्दु (Action Points)

| Sr. No. | Issue | Status | Required Action |
|---|---|---|---|
| 1. | Recovery of Bank dues under RC filed cases and permission/ possession of properties etc. in SARFAESI cases filed by the Banks | The recommendations of the Sub– Committee of SLBC (UP) on Recovery issues were placed for discussion in the Meeting. During the discussions 3 important issues have emerged wherein the active support & cooperation of the State Govt. is felt and has been requested upon as per following status :<br>➢ 8.84 Lac RCs amounting to Rs.6163.00 Crores approximate of different Banks are pending in the State. Computerization of the RCs in the State has been done during 2012-13 and a list of top -50- RCs per district has also been made available to the DMs and DIF by Banks. However, the recovery under RC filed accounts is very meagre.<br>➢ Approximately -1800- applications of different Banks under SARFAESI Act are pending for long for permission/ possession of the described property by the District Magistrates of different districts in the State. Due to non-disposal of the applications for long, the recovery of Bank dues is held up and there is an urgent need for creating a conducive recovery climate in the State by providing necessary support.<br>➢ Under SARFAESI Act cases, the Banks are required to pay heavy charges for the Police Force which is made available in the process of taking the physical possession of the properties in question. The rationalization of this issue across the State and specific guidelines for the same are necessary.<br>➢ The State Govt. instructions in this regard have been issued to the District Magistrate on 21.03.2018 and 16.05.2018. Moreover, these issues are being regularly discussed during the Sub – Committee Meetings of SLBC (UP) under Convenorship of Allahabad Bank. | All Banks have been requested to follow up with Revenue authorities for persuing the RC filled cases and effecting the Recovery in the same. The Banks also are requested to submit the details of the cases filled under SARFAESI Act, 2002 where the permission is pending from the District Collectors and which are pending for more than 60 days. Such cases may also be taken up at the State Head quater with the Revenue Authorities of GoUP by the respective Banks.<br>(Action: All Banks & the DIF) |
| 2. | Functioning of Business Correspondents (BCs) and display of their details at the link branch etc. | ➢ As many as 21,413 BCs are functioning in the State to cover 27,628 SSAs. These BCs are providing various Banking Services to the masses in different parts of the State. However, instances have come to the notice that either the BCs become inactive/ defunct or the public is not well versed with the services being rendered by them in their area of operation. Hence, a need is felt to display the details of BCs in their link branch so that the public may get a first hand information about them.<br>➢ The issue has been taken up with the Banks vide SLBC letter no. LZ:44:SLBC:141 dated 17.05.2018 interalia requesting Banks for appointment of new BCs, replacement of inactive BCs, display of relevant information about the activities/ scope of BCs and their photographs at links Branch(es). Barring -5- Banks, the details are awaited from other Member Banks and the matter is being followed up with for the compliance. | All Banks have again been requested to display the details of BCs at link branch of the banks with photograph of BC and the works which are being carried out by them and also the works which are not permitted to be performed by them so that customers of the bank are made aware about functioning of the BCs and may not be subjected to any cheating.<br>(Action: All Banks) |
| 3. | Effective Implementation | ➢ The PMMY & Stand Up India (SUI) Schemes are Govt. of India sponsored Schemes and were launched on 08th April | All Banks are requested to have a focused attention for |



बैंक ऑफ़ बड़ौदा BANK OF BARODA अंचल कार्यालय ZONAL OFFICE (EUP ZONE) LKO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) & Stand Up India (SUI) Schemes in the State in order to achieve the set Annual Targets | 2015 and 05th April 2016 respectively.<br><br>➢ Under PMMY, Annual Targets are received by Banks for State from their Corporate Office which in turn are distributed up to the Branch Level. Under SUI, every branch is required to finance -1- SC/ ST and -1- Women Enterpreneur. Under PMMY, the maximum Ceiling of the loan per beneficiary is Rs. 10 lacs while under SUI, the projects ranging over Rs. 10 lac up to Rs. 1 Crore are covered.<br><br>➢ The Progress under PMMY during 2016-17 and 2017-18 stood at the level of 91.27% and 102.20% respectively against the set Annual Targets which indicate that Banks are actively involved in the process of scheme implementation.<br><br>➢ All Banks are requested to have a focus on Stand Up For the FY 2018-19, Banks have disbursed ₹ 6567.36 Crores against the set Annual Target of Rs. 14698.45 Crores thereby achieving 44.68% progress as on 02.11.2018.<br><br>➢ However, under Stand Up India (SUI) scheme against the total target of -32514-, the sanction and disbursement has been made in -8364- (25.72%) & -6882- (21.16%) accounts respectively as at 12.11.2018. | achievement of the set targets under PMMY and SUI Schemes<br><br>(Action: All Banks) |
| 4. | Implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) to fulfill the National objective of Housing for all. | ➢ The Scheme was launched by Hon'ble Prime Minister on 17.06.2015 and has four verticals viz. "In Situ" Slum Development, Affordable Housing though Credit Linked Subsidy, Affordable Housing in Partnership, and Subsidy for beneficiary- led individual house construction. The Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) is being implemented through Primary Lending Institutions (PLI) wherein National Housing Bank and HUDCO have been identified as Central Nodal Agency (CNA). The Scheme covers EWS, LIG and MIG Sections of the society and covers various loan components up to Rs. 18 lacs.<br><br>➢ The Government is placing lot of thrust on Housing Sector. This scheme being implemented through Banks (with a Subsidy component) is being closely monitored at all levels.<br><br>➢ As at September 2018 as many as -19068- accounts have been disbursed under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) by different Bank.<br><br>➢ The progress under the scheme is being reviewed at the highest level during State Level Sanction and Monitoring Committee Meetings (SLSMC) under Chairmanship of Chief Secretary, GoUP. Last Meeting of SLSMC held on 24.09.2018.<br><br>➢ HUDCO has provided a list of applicants from -480- Nagar Nigam aspiring for loan under the scheme. The same has been shared with the Banks for their further necessary action. | Housing is an important sector for the masses and the GoI/ GoUP is placing a lot of thrust on the subject matter, it is requested that the Banks do mobilize and finance the loans to the sector and all applications are considered on merit for finance.<br><br>It is also requested that the Nodal Agencies do extend a helping hand to the Banks by way of forwarding the applications of target group.<br><br>(Action: All Banks ; Central Nodal Agency) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Submission of the success stories of beneficieries of various schemes for presentation during the SLBC Meetings | ➢ As per the Revamp Lead Bank Scheme, it is advised that all Banks do submit success stories of the beneficieries financed by them under different schemes and the same be presented during the SLBC Meetings. | All Banks are requested to continue to submit success stories of the entreprenours financed by them to SLBC so that the same may be compiled and submitted to the forum on regular basis.<br><br>(Action: All Banks) |
| 6. | Implementation of -100- days MSME Support & Outreach Programme | The implementation of -100- days MSME Support and Outreach Programme launched by Govt. of India is applicable in -9- Districts of the State. With a grand gala inauguration of the event on 2nd November 2018, all Districts are now engaged in the process. This GoI initiatives is going to give a boost to the MSME Sector in the State with the active support of all Banks and other stake holders.<br><br>A target of 2,60,623 units is fixed for -9- districts of our State which are to be touched upon. A Dashboard has been created for the purpose to upload the data on regular basis in case of all -10- deliverables. The weekly camps are being organized in the districts and regular monitoring is being done at the highest level. | All Banks are requested to put their best efforts to achieve the targets on or before the set time lines.<br><br>(Action: All Banks) |
| 7. | Opening of CBS enabled Banking Outlet/ B&M Branches in unbanked Rural Centres having population 5000 & Above | A Sub-Committee of SLBC (UP) is working on this aspect which is a flagship programme of the State Government.<br><br>After achieving the goal for setting up Banking Outlets in -571- identified centres, in the IInd Phase, the Sub-Committee during its Meeting dated 17.11.2018 has crystalized a list of -457- centers (of 48 Districts) for the expansion plan and the centres have been allotted to Banks for opening of CBS enabled Banking Outlet/ B&M Branches.<br><br>All concerned Banks are requested to complete the exercise by 31.03.2019. | All Banks are requested to open the Banking Outlets/ B&M Branches latest by 31.03.2019.<br><br>(Action : All Banks) |

# List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 03.12.2018

## PARTICIPATION SHEET

| Sr. No. | Organization | Designated Member | Status of Participation | Participating Authority & Contact Details: Designation | Name | Contact No. | Email_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai | Chairman & Managing Director / Executive Director | Yes | Executive Director | Shri Vikramaditya Singh Khicchi | | |
| 2 | Bank of Baroda, Lucknow Zone | General Manager | Yes | General Manager | Shri Ram Jass Yadav | 0522-6677607 | zm.upu@bankofbaroda.com |
| 3 | Reserve Bank of India, Lucknow | Regional Director | Yes | Regional Director | Shri Ajay Kumar | | |
| 4 | | | | General Manager | Shri Yogesh Dayal | | yogeshdayal@rbi.org.in |
| 5 | | | | Asstt. General Manager | Shri R K Singh | 8887171993 | rksingh2@rbi.org.in |
| 6 | | | | Manager | Shri Kunal Mohan | 9519916345 | kunalmohan@rbi.org.in |
| 7 | | | | Manager | Shri Acharaya Sagar Vikas | 8210108736 | asvikash@rbi.org.in |
| 8 | NABARD, R.O., Lucknow | Chief Gen. Manager | Yes | Chief General Manager | Shri A K Singh | 9819418150 | ak.singh@nabard.org |
| 9 | | | | General Manager | Shri M Mukherjee | 7506927894 | monomoy.mukherjee@nabard.org |
| 10 | | | | Manager | Ms. Richa Bajpai | 9794106221 | richa.bajpai@nabard.org |
| 11 | State Bank of India | Chief Gen. Manager/Gen. Manager | No | Dy. General Manager | Shri Pradeep K Sharma | 7600035355 | dgm.abu1.lholuc@sbi.co.in |
| 12 | | | | Asstt. General Manager | Shri Kamla Pati Tiwari | 7706909222 | agmlb.lholuc@sbi.co.in |
| 13 | | | | Chief Manager | Shri Amit Gupta | 9041048894 | agmlb.lholuc@sbi.co.in |
| 14 | Allahabad Bank, Lucknow | Field Gen. Manager/ State Head | Yes | Field. General Manager | Shri Ravinder Singh | 9815742224 | fgmo.luc@allahabadbank.in |
| 15 | | | | Chief Manager | Shri Ashok Raj | 9467303306 | ashok.raj@allahabadbank.in |
| 16 | Union Bank of India, Lucknow | Gen. Manager/ State Head | Yes | General Manager | Shri Lal Singh | 9920123101 | fgm.lucknow@unionbankofindia.com |
| 17 | | | | Senior Manager | Shri Anand Kumar | 9892260171 | anand.choudhary@uninbankofindia.com |
| 18 | Syndicate Bank | Field General Manager | No | Asstt. General Manager | Shri A K Prasad | 8005493994 | zo.lucknow@syndicatebank.co.in |
| 19 | | | | Senior Manager | Shri S P Yadav | 8004912850 | fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in |
| 20 | Bank of India | Gen. Manager/ State Head | Yes | General Manager | Shri Brij Lal | 7541813901 | nb.north2@bankofindia.co.in |
| 21 | | | | Asstt. General Manager | Shri R K Sharma | 9425308514 | nb.north2@bankofindia.co.in |
| 22 | Central Bank of India | Field Gen. Manager/ State Head | No | Dy. General Manager | Shri M K Srivastava | 7354889121 | dgm.luck20@centralbank.co.in |
| 23 | | | | Senior Manager | Shri Naveen Kumar | 9930304592 | rdluckzo@centralbank.co.in |
| 24 | Punjab National Bank | Field Gen. Manager/ State Head | Yes | General Manager | Shri Vivek Jha | 7060302340 | vivekjha@pnb.co.in |
| 25 | | | | Asstt. General Manager | Shri D R Sharma | 9821100628 | dr.sharma@pnb.co.in |
| 26 | | | | Senior Manager | Ms. Swati Shukla | 8800138377 | swati.shukla@pnb.co.in |
| 27 | | | | Officer | Shri Nand Kishore | 8173000132 | nandkishore@pnb.co.in |
| 28 | Canara Bank | Chief Gen. Manager/ State Head | Yes | General Manager | Shri U K Sharma | 9473527060 | umeshkumarsharma@canarabank.com |
| 29 | | | | Senior Manager | Shri Atul Kumar | 9997699945 | atulkumar@canarabank.com |
| 30 | Indian Bank | Dy. Gen. Manager/ State Head | Yes | Zonal Manager | Shri N Anand Kumar | 9432013447 | anandkumar30701@indianbank.co.in |
| 31 | | | | Chief Manager | Shri Ajay Kumar Chaubey | 7233002205 | |
| 32 | Dena Bank | Dy. Gen. Manager/ State Head | Yes | Dy. General Manager | Shri Suresh Buntolia | 9721459111 | sbuntolia@denabank.co.in |
| 33 | | | | Senior Manager | Shri Prerit Agarwal | 9721459202 | rdd.lucknow@denabank.co.in |
| 34 | Punjab & Sind Bank | Dy. Gen. Manager/ State Head | No | Manager | Ms. Yasmin Khan | 8874228527 | zo.lucknow@psb.co.in |
| 35 | Corporation Bank | Dy. Gen. Manager/ State Head | No | Chief Manager | Shri Tej Pal Singh | 9426302606 | tejpal@corpbank.co.in |
| 36 | | | | Senior Manager | Shri S K Singh | 8052113909 | cb8817agri@corpbank.co.in |
| 37 | Andhra Bank | General Manager/ State Head | Yes | Asstt. General Manager | Shri V S Rao | 7311106709 | zmluck@andhrabank.co.in |
| 38 | Indian Overseas Bank | Chief Regional Manager/State Head | No | Asstt. Gen. Manager | Shri V Chandramohan | 8887145493 | iob@csco.co.in |
| 39 | | | | Senior Manager | Shri Samir Tiwari | 9450365872 | 35387@iobnet.co.in |
| 40 | Oriental Bank of Commerce | Zonal Head | No | Dy. Gen. Manager | Shri Sudhanshu Shekhar Das | 8051807700 | cmh.lko@obc.co.in |
| 41 | | | | Manager | Shri Ashish Pandey | 8896648820 | rural-lko@obc.co.in |
| 42 | United Bank of India | Chief Regional Manager | No | Asstt. Gen. Manager | Shri Debasish Gangopadhyay | 8585022601 | debasishg@unitedbank.co.in |
| 43 | | | | Manager | Shri B N Roy | 9453018180 | devcentral@unitedbank.co.in |
| 44 | UCO Bank | Zonal Head | No. | Dy. Zonal Head | Shri Anant Sharma | 9530253651 | zo.lucknow@ucobank.co.in |
| 45 | | | | Senior Manager | Shri Pradeep Kr. Mishra | 941516843 | zo.lucknow@ucobank.co.in |
| 46 | Vijaya Bank | Gen. Manager | No | Asstt. General Manager | Shri Ashok Kumar | 8168465758 | lucknow@vijayabank.co.in |
| 47 | | | | Senior Manager | Shri K K Singh | 7572024243 | creditplucknow@vijayabank.co.in |
| 48 | Bank of Maharashtra | State Head | Yes | Zonal Manager | Shri R T Parulekar | 9004774819 | zmlucknow@mahabank.co.in |
| 49 | | | | Chief Manager | Shri S K Jha | 7084150006 | cmcpc-luc@mahabank.co.in |
| 50 | Baroda U.P. Gramin Bank | Chairman | Yes | Chairman | Shri D.P. Gupta | 7704809183 | chairman@barodauprrb.co.in |
| 51 | Allahabad U.P. Gramin Bank | Chairman | Yes | Chairman | Shri Mithilesh Kumar | 9647572558 | |
| 52 | Gramin Bank of Aryavart | Chairman | Yes | Chairman | Shri S B Singh | 9594718299 | chairman@gba-rrb.com |
| 53 | Prathma Bank | Chairman | Yes | Chairman | Shri Rama Naik K | 8954607080 | chairman@prathamabank.org |
| 54 | Serve U.P. Gramin Bank | Chairman | Yes | Chairman | Shri A K Sharma | 8130167878 | anils2@pnb.co.in |
| 55 | Purvanchal Bank | Chairman | Yes | Chairman | Shri A K Sinha | 7571810001 | chairman@purvanchalbank.co.in |
| 56 | Kashi Gomti Samyut Gramin Bank | Chairman | No | General Manager | Shri Rajeev Srivastava | 9984970001 | gmkgsg@kgsgbank.co.in |
| 57 | U.P. Cooperative Bank Ltd. | Managing Director | No | Chief General Manager | Shri Hridya Ram | 7388802800 | upcbidd@gmail.com |
| 58 | | | | Asstt. Manager | Shri Manish Kumar Nigam | 8090084501 | manishkumar5673@gmail.com |
| 59 | UPSGVB | Managing Director | No | No Participation | | | |
| 60 | Axis Bank | Circle Head | Yes | Senior Manager | Smt Mitali Savant | 9889016931 | mitali.savant@axisbank.com |
| 61 | HDFC Bank, Lucknow | Zonal Head | No | Senior Manager | Shri Basant Kumar | 9792330000 | basant.kumar@hdfcbank.com |
| 62 | | | | Nodal Officer | Shri Sameer Tiwari | 9873816373 | sameer.tiwari@hdfcbank.com |
| 63 | Nainital Bank Ltd., Nainital | Chairman & CEO | No | No Participation | | | |

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0 ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO. अंचल कार्यालय (पू0उ0प्र0 अंचल), लखनऊ

| Sr. No. | Organization | Designated Member | Status of Participation | Participating Authority & Contact Details | | | Email_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Designation | Name | Contact No. | |
| 64 | IDBI Bank Ltd. | General Manager | No | Asstt. General Manager | Shri Manish Kumar Nigam | 8930111292 | manish.nigam@idbi.co.in |
| 65 | ICICI Bank, Lucknow | Regional Head | No | Regional Head | Shri Anil Kumar | 8003295857 | anilr.kumar@icicibank.com |
| 66 | | | | State SLBC Head | Shri Aftab A Khan | 8756888141 | aftab.alam@icicibank.com |
| 67 | The Karnataka Bank, New Delhi | Dy. Gen. Manager | No | Sr. Br. Manager | Shri Sandeep Kumar | 9839222575 | lucknow@ktkbank.com |
| 68 | Kotak Mahindra Bank | State Head | No | Sr. Manager | Shri Sanjay K Srivastava | 9235396977 | sanjay.kumar.srivastava@kotak.com |
| 69 | Indusind Bank | State Head | No | No Participation | | | |
| 70 | Federal Bank | State Head | Yes | AVP & Area Head | Shri Anand Kumar | 9651192042 | anandkumar@fedeeralbank.co.in |
| 71 | South Indian Bank | State Head | No | No Participation | | | |
| 72 | Govt. of U.P. | Chief Secretary | Yes | Chief Secretary | Dr. Anoop Chandra Pandey, IAS | | |
| 73 | Agriculture | Principal Secretary | Yes | Principal Secretary | Shri Amit Mohan Prasad, IAS | | |
| 74 | Handloom & Textile Deptt. | Principal Secretary | No | Asstt. Commissioner | Shri Manoj Kant Garg | 9450726882 | adilkohl@gmail.com |
| 75 | UPSRLM | Misson Director | No | Joint Mission Director | Shri V K Bhagwat | 9415424754 | mdsrlmup9@gmail.com |
| 76 | | | | State Project Manager | Shri Om Prakash Chaturvedi | 6392093782 | upsrlmspmmt@gmail.com |
| 77 | Social Welfare | Principal Secretary | No | Jt. Secretary | Shri Bhagwati Prasad | 9454412718 | |
| 78 | SIDBI | State Head/General Manager | Yes | General Manager | Shri Arup Kumar | 9870508754 | arupkumar@sidbi.in |
| 79 | MSME Kanpur | Director | No | Special Secretary | Shri Raveesh Gupta | 9456922200 | raveeshgupta@gmail.com |
| 80 | Planning Department | Principal Secretary | No | Special Secretary | Shri R N S Yadav | 9415288891 | ramnarayansingh.a@gmail.com |
| 81 | Board of Revenue | Commissioner & Secretary, GoUP | No | Dy. Land Reform Commissioner | Shri J B Yadav | 0522-2217108 | borlko@nic.in |
| 82 | Directorate of Industries, Kanpur | Commissioner & Director, GoUP | Yes | Commissioner & Director | Shri K Ravindra Nayak, IAS | 7234805001 | dikanpur@gmail.com |
| 83 | | | | Asstt. Commissioner | Shri Mukesh Kumar | 7234805024 | diup123@gmail.com |
| 84 | Directorate of Instt. Finance (DIF) | Director General | Yes | Director General | Shri Shiv Singh Yadav | | |
| 85 | | | | Addl. Director | Shri Rakesh Krishna | 7651905462 | |
| 86 | | | | Joint Director | Shri Pramod Kumar | 8005134529 | |
| 87 | | | | Reserch Officer | Dr. Raghuvendra | 9415654000 | |
| 88 | UP SC Finance & Dev. Corpn. | Managing Director | No | General Manager | Shri R P Singh | 9415255269 | |
| 89 | Directorate of Agriculture | Director | No | Director Agri. Stat, UP | Shri V K Singh | 9415093148 | agristatup@gmail.com |
| 90 | Khadi & Village Industry Comm. | State Director | Yes | State Director | Shri R S Pandey | 9454364925 | kvic.lko2011@gmail.com |
| 91 | | | | Asstt. Director - II | Shri Ashutosh Kumar Singh | 9415463417 | ashutoshkvic1973@gmail.com |
| 92 | National Horticulture Board | Director | No | Sr. Horticulture Officer | Shri A K Mishra | 9822703510 | nhblko@rediffmail.com |
| 93 | Khadi & Village Industry Board | Chief Executive Officer | No | Dy. CEO | Shri Hari Ram Singh | 7408410716 | ceoupkvib@gmail.com |
| 94 | State Urban Development Agency | Director | No | S.M.M. | Shri O R Singh | 9412270501 | nulmup@gmail.com |
| 95 | Police Headquarter | Director General | No | Add. S P | Shri Maan Singh Chauhan | 9454404915 | igcrime-up@nic.in |
| 96 | National Housing Bank | Regional Manager/DGM | No | Regional Representative | Shri Sharat Bhattacharya | 9205137011 | sharat.bhattacharya@nhb.org.in |
| 97 | UP Bhoomi Sudhar Nigam | Director | No | No Participation | | | |
| 98 | Udyog Bandhu | Executive Director | No | No Participation | | | |
| 99 | HUDCO | General Manager | Yes | Jt. General Manager | Shri R K Srivastava | 9450932215 | hudcolucknow@gmail.com |
| 100 | RSETI, MoRD | State Project Co-ordinator | No | No Participation | | | |
| 101 | LIC of India | Regional Manager | No | Sr. Branch Manager | Shri H S Sachdeva | 8299822872 | hs.sacgdeva@licindia.com |
| 102 | Oriental Insurance Co. Ltd. | Regional Manager | No | Asstt. Manager | Shri C S Chaturvedi | 9415426329 | cs.chaturvedi@orientalinsurance.co.in |
| 103 | Deptt. Of Post | Chief Post Master General | No | Asstt. Director (RI) | Shri Sandeep Jaiswal | 9453016288 | ad5termlu-up@nic.in |
| | | | | Special Invities | | | |
| 104 | EPFO | Director | No | Asstt. CPF Commissioner | Shri Shalabh Dubey | 9452295310 | ro.lucknow@epfindia.gov.in |
| 105 | UIDAI | Asstt. Director General | No | No Participation | | | |
| 106 | UPICO | Managing Director | Yes | Managing Director | Shri Pravin Singh | 9454833333 | pravin.singh@upico.in |
| 107 | Animal Husbandry | Director | No | Jt. Director | Dr. P K Pradhan | 9532673506 | dir-ah.up@nic.in |
| | | | | Dy. Director | Dr. Todarmal | 6452237571 | dir-ah.up@nic.in |
| 108 | Lead District Managers of -9- MSME Outreach & support Districts | Firozabad | | Lead District Manager | Shri S K Khandelwal | 8130799550 | sudeepk@sbi.co.in |
| 109 | | Agra | | Lead District Manager | Shri Suresh Ram | 8360997986 | lboagra@canarabank.com |
| 110 | | Bhadohi | | Lead District Manager | Shri Amitava Sen Gupta | 9918502505 | ldmgyanpur@unionbankofindia.com |
| 111 | | Varanasi | | Lead District Manager | Shri Mithilesh Kumar | 9918900938 | ldm.varanasi@unionbankofindia.com |
| 112 | | Meerut | | Lead District Manager | Shri Abinash Tanti | 9412782538 | ldo.meerut@syndicatebank.co.in |
| 113 | | Kanpur Nagar | | Lead District Manager | Shri A K Verma | 7388025964 | ldm.kanpurnagar@bankofbaroda.com |
| 114 | | Moradabad | | Lead District Manager | Shri Satish Gupta | 9412774705 | ldm.moradabad@syndicatebank.co.in |
| 115 | | Saharanpur | | Lead District Manager | Shri Rajesh Chaudhary | 8171979243 | ldmsre@pnb.co.in |
| 116 | | Unnao | | Lead District Manager | Shri Surya Prasad Sah | 9430158394 | leaddistrictmanagerunnao.kanpur@bankofin |
| 117 | Bank of Baroda | | | Dy. General Manager | Shri K D Bansal | | |
| 118 | | | | Asstt. Gen. Manager | Shri Sanjeev Gupta | 0522-6677722 | slbc.up@bankofbaroda.com |
| 119 | | | | Chief. Manager | Shri K. K Mathur | 0522-6677721 | slbc.up@bankofbaroda.com |
| 120 | | | | Senior Manager | Shri B K Gupta | 0522-6677730 | ps.upu@bankofbaroda.com |
| 121 | | | | Manager | Shri Shailendra Kr. Sharma | 0522-6677717 | |
| 122 | | | | Officer | Shri Rakesh Kumar Srivastava | 0522-6677725 | |
| 123 | | | | Officer | Smt. Sheetal | 0522-6677694 | |
| 124 | | | | Officer | Ms Anjali Singh | 0522-6677726 | |
| 125 | | | | Business Associates | Ms. Shikha Tripathi | 0522-6677726 | |
| 126 | | | | Business Associates | Shri Arun Kumar Agarwal | 0522-6677725 | |